बिजली बोर्ड ने वर्ष 1969-70 में कृषि प्रयोजनों के हेतु पम्पिंग सैटों के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त धन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1969-70 के लिए 2 करोड़ रुपये की और सहायता मांगी गई है । क्योंकि 1969-70 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है, इस लिए इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मध्य प्रदेश में व्यक्तियों और कंपनियों के विरुद्ध बकाया पांच लाख रुपये से अधिक राशि पर कर

9232. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन व्यक्तियों अथवा फर्मों के विरुद्ध 5 लाख अथवा अधिक राशि के कर (आयकर, सम्पदाशुल्क, धनकर, उपहार-कर, तथा व्यय-कर,) बकाया हैं ।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक व्यक्ति अथवा कंपनी के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) उक्त राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई या किये जाने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

कोसी बांध के बीच ग्रामीणों का बसाया जाना

9233. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोसी पर बने बांधों के बीच के गांवों की संख्या कितनी है तथा उनकी जनसंख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त लोगों के पुनर्वास के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 1.5 लाख जनसंख्या वाले 303 ग्राम कोसी के तटबन्धों के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम कोसी परियोजना

9234. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी बार और किन-किन ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का उद्घाटन किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना की कार्यान्विति के बारे में जनता में बहुत क्षुब्धता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसकी कार्यान्विति के बारे में नेपाल सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित करना चाहती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दो बार —1962 में बिहार के मुख्य मन्त्री द्वारा और 1965 में भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा ।

(ख) से (घ). पश्चिम कोसी नहर के लिए नेपाल प्रदेश में भूमि के अधिग्रहण के लिए नेपाल सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है ।

Goa Chief Minister's Visit Abroad

9235. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Goa along with his daughter had gone abroad in December last ;

(b) the places he visited and the purpose of his visit ;

(c) the foreign exchange released to him and his daughter ;

(d) whether Government's attention has also been drawn to the articles contributed by the Chief Minister of Goa about his tours abroad and the amount he had spent there ; and

(e) whether Government have ascertained the extent to which the expenses incurred by him were in confirmity with the foreign exchange released to him ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) U S.A. for visiting his sister ;

(ii) Beirut, Rome. Yugoslavia, London, Tokyo and Hongkong. The visit to Yugoslavia was for attending the launching ceremony of cargo ship 'Damodar Tanabe'. The visit to Japan was to see the various development works.

(c) No foreign exchange was released.

(d) It has been brought to the notice of the Government that on his return, the Chief Minister had contributed two articles in the local daily "Gomantak".

(e) The visit to U.S.A. was on the hospitality of Shri Bandodkar's sister's husband and was approved by the Reserve Bank. For the visit to the other places, prior permission of the Reserve Bank should have been obtained, particularly in regard to the visits to Yugoslavia, Tokyo and Hongkong. The halts at Beirut, Rome and possibly London could be treated as normal *en route* halts for which a total time of 3/7 days is allowed.

Retired Officials of Public Undertakings Serving in Private Firms

9236. SHRI P. VISWAMBHARAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that retired senior Officials of public undertakings accept appointments in private firms with which they had financial dealings when they were in the service of the public undertakings :

(b) whether Government have taken any decision and framed rules prohibiting retired officials of public undertakings serving private firms ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Government are aware that there have been some cases where Senior Officials of the Public Undertakings have taken up appointments in private firms after retirement. Of these, in some cases, the private firms concerned had contracts with public undertakings where the officials had been serving earlier.

(b) There are no rules prohibiting retired officials of public undertakings serving private firms. However, to safeguard the interests of Public Undertakings, orders have been issued whereby a Public Undertaking is required to obtain the approval of the Board of Directors before giving contracts to private firms, where a top executive who has retired from the Public Undertaking is employed, for a period of two years following the retirement of that officer.

(c) Does not arise.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की पदोन्नतियां

9237. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-एस्टेबलिशमेंट (सी०) के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके मंत्रालय में 15 मार्च, 1969 तक विभागवार, अनुभागवार तथा वर्गवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को उनके लिए आरक्षित पदों पर पदोन्नतियां की गईं ; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों के पदनाम क्या हैं और उन विभागों के नाम क्या हैं जहां वे कार्य कर रहे हैं ?